VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2368)

Name of Candidate	Ishwar lal Gurjar		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1295818.
Center	Jaipur	Date	9 sep, 2024

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended	Strongly Recommended

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

For one-to-one mentoring session on this copy, call us at 7042691891 or send an email to appointment@visionias.in

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q1. न्यायालयों द्वारा की जा रही व्याख्या के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे का विस्तार हुआ है। न्यायालय के प्रासंगिक पूर्ववर्ती निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The evolving interpretation by the courts have led to the expansion of the scope of the Right to Life and Personal Liberty under Article 21 of the Indian Constitution. Discuss with the help of relevant case laws. (Answer in 150 words) 10

गोपालन v/s UOI 1950 वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-21 की संकीर्ण व्याख्या करते हुए जीवन के अधिकार को जीवित रहने तक ही बताया। लेकिन 1978ई. मेनका गांधी v/s UOI वाद में अनुच्छेद-21 की व्यापक व्याख्या करते हुए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की सम्यक प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करते हुए। जीवन को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार बताकर व्याख्या की

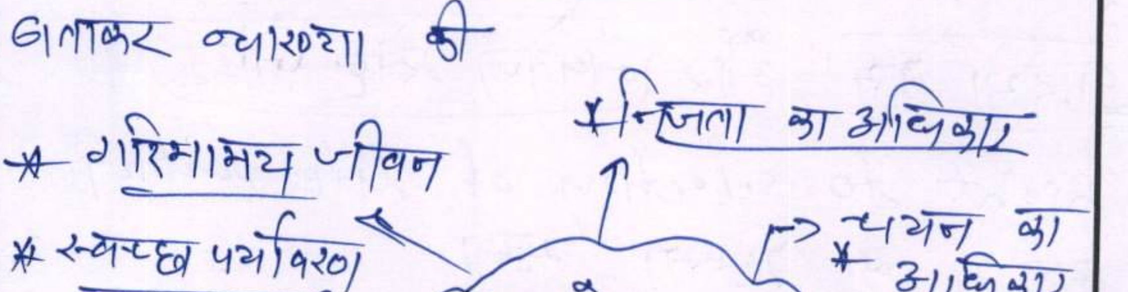

अनुच्छेद-21 के विस्तार में न्यायालय की भूमिका

(1) के. एस पुट्टास्वामी वाद - 2017 में जीवन के अधिकार में निजता के अधिकार को शामिल
(2) एम. सी. मेहता वाद 1987 - स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को एक मूल अधिकार माना।
(3) हुसैनारा खातून वाद - विचाराधीन कैदियों को त्वरित सुनवाई अधिकार को अनु. 21 का हिस्सा माना।
(4) एम. के रणजीत सिन्हा - 2024 वाद में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्ति को अनु. 14 व 21 का हिस्सा माना
(5) हादिया केस और नवतेज सिंह जौहर में Right to selection of life partner को अनु. 21 का हिस्सा माना

अतः न्यायालय ने अनु. 21 की विस्तारपूर्ण व्याख्या कर इसे संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा बनाकर जीवंत समाज की आकांक्षा को पूरा किया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8A भारत में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को किस प्रकार सुरक्षित रखती है। विश्लेषण कीजिए (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Analyse how Section 8A of the Representation of the People Act, 1951 preserves the integrity of the electoral process in India. (Answer in 150 words) 10

RPA एक्ट -1951 संविधान में अनु. 326 के तहत निष्पक्ष, स्वतंत्र व समयबद्ध चुनाव के लिए ECI को अनेक शक्तियाँ प्रदान करता है। धारा-8A में भ्रष्ट आचरण को रोकने के प्रावधान है।

धारा-8A और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता

(1) धर्म और जाति के नाम पर वैमनस्य फैलाने और हेट स्पीच को रोकता है।

(2) उम्मीदवार को 2 वर्ष से अधिक कारावास की स्थिति में 6 वर्ष तक चुनाव में भाग लेने से रोकता है। राजनीति के अपराधीकरण को कम करता है।

(3) चुनावी भ्रष्टाचार को कम करता है वोट के लिए पैसा बाँटने पर प्रतिबंध

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने हेतु धारा-8A का प्रयोग किया
यथा - सरकारी ठेकेदारी में हिस्सेदारी पर प्रतिबंध

(5) दिवालिया और भ्रष्ट आचरण दोषी पाए जाने पर चुनाव पर रोक लगाना।

* राजनीतिक निष्पक्षता ← धारा-8(A) की उपयोगिता → चुनावी लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण
* सहभागी लोकतंत्र ← धारा-8(A) की उपयोगिता → क्लीन इलेक्शन
* धारा-8(A) की उपयोगिता → जवाबदेह चुनाव

अतः RPA-एक्ट 1951 की धारा-8(A) को और अधिक सुदृढ़ कर लीली थॉमस वाद, सुब्रमन्यम वाद और ADR वाद के निर्णयों के अनुसार चुनावी पारदर्शिता और नैतिकता को बना देना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q3. भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची को प्रारंभ में किन उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया था? क्या उच्चतम न्यायालय नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी कानून की समीक्षा कर सकता है? न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

With what objectives was the Ninth Schedule of the Indian Constitution initially introduced? Can the Supreme Court review a legislation that has been placed in the Ninth Schedule? Discuss with the help of case laws. (Answer in 150 words) 10

प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद - 31(B) में 9वीं अनुसूची को भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देने हेतु किया गया।

9वीं अनुसूची का महत्व

(1) मौलिक अधिकार (संपत्ति के अधिकार अनु. 19f) और नीति-निर्देशक तत्वों (अनु. 38 & 39) में टकराव को रोकना

Eg- शंकरी प्रसाद v/s राजस्थान राज्य

(2) चरणक्रम दुरई राजनवाद के बाद उपस्थित उलझनों को दूर करना।

(3) भूमि सुधार - जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी को लागू करने के लिए

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उच्चतम न्यायलय के निर्णय

(1) वामन राव वाद में उच्चतम न्यायलय ने माना की केशवानंद भारती वाद 1973 से पूर्व के संशोधनो पर न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है।

(2) आई आर. कोहलोट वाद 2007 में उच्चतम न्यायलय ने माना की 9 वी अनुसूची में शामिल विषयो की समीक्षा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नहीं की जा सकती लेकिन संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन करने पर न्यायिक समीक्षा संभव है।

9 वी अनुसूची में 200 से अधिक अधिनियम शामिल है जो इसके मूल उद्देश्य से विचलन उत्पन्न करते है अत: इसका समय के साथ अद्यतन करना जरूरी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q4. ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) द्वारा प्रदान की जाने वाली विवादों के उचित, त्वरित और प्रभावी समाधान तक पहुंच कई चुनौतियों से घिरी हुई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Online Dispute Resolution's (ODR) promise of access to just, speedy and effective resolution of disputes is beset with several challenges. Discuss. (Answer in 150 words) 10

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) में ODR एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा है जहां ई-कोर्ट और वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से उचित व त्वरित समाधान प्रस्तुत किया जाता है।
eg- गुजरात HC द्वारा जस्टिस क्लॉक को अपनाना।

ODR में चुनौतियां

1) डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव है।
eg- 25% कोर्ट में रिकॉर्ड रूम का अभाव है। साथ ही 17% कोर्ट रूम में इंटरनेट कनेक्शन नहीं।

2) डिजिटल साक्षरता के अभाव के कारण वकील, पुलिस और जज

तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं है।

(3) ऑनलाइन जज और विशेषज्ञता का अभाव है। यू- डोमेन नॉलेज की कमी के कारण निचली अदालतों में ODR में मुश्किल

(4) डिजिटल डिवाइस - भारत में ग्रामीण स्तर पर (31%) लोग ही इंटरनेट का use करते है।

(5) आपराधिक न्याय प्रणाली की जटिलता के कारण विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-गवाही में कमी

आगे की राह

↳ * ई-कोर्ट स्कीम के तहत वर्चुअल कोर्ट और ODR प्रणाली को बढ़ावा देना

* टेली लॉ सर्विस को बढ़ावा देना

* नेशनल क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और जस्टिस क्लॉक जैसा डिजिटल ढांचा तैयार करना। अतः (5.1 करोड़) पेंडिंग केस के लिए ODR प्रभावी होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q5. केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यालय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के कारण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम निरर्थक हो गया है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The Right to Information (RTI) Act has fallen into redundancy owing to the issues faced by the Office of the Central Information Commission. Analyse. (Answer in 150 words) 10

RTI के तहत (3 माह) से अधिक आवेदन लंबित है। केन्द्रीय सूचना आयोग की धीमी और उदासीन कार्यप्रणाली ने RTI एक्ट 2005 के उद्देश्य को धूमिल करने का काम किया है।

केन्द्रीय सूचना आयोग की प्रमुख समस्याएं और कारण

- * RTI कार्यकर्ताओं की हत्या से निरुत्साह
  eg- अब तक 80 RTI एक्टिविस्ट की हत्या
- * जनसूचना अधिकारियों के रिक्त पद और प्रशिक्षण का अभाव
- * CIC के फंड और मानव संसाधन का अभाव
- * राजनीतिकरण के कारण हस्तक्षेप
- * RTI और आधिकारिक सीक्रेसी एक्ट 1923 में टकराव
- * तकनीक का कम प्रयोग
- * केन्द्रीय सूचना आयोग (संशो) अधिनियम में स्वायत्तता का अभाव
  eg- कार्यकाल की सुरक्षा नहीं

समाधान -> * CIC को अधिक स्वायत्तता देना

* तकनीक द्वारा कार्यालय की क्षमता बढ़ाना ex- ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन की प्रक्रिया

* सूचनाओं का श्रेणीकरण, सूचीकरण और डिजीटलीकरण करके सूचना तक पहुँच सुधारना

* II ARC ने RTI को सुशासन के ताले की चाबी कहा है। अतः जागरूकता द्वारा स्थानीय स्तर पर लागू करना ex- ग्राम पटवारियों के स्तर पर RTI का प्रयोग

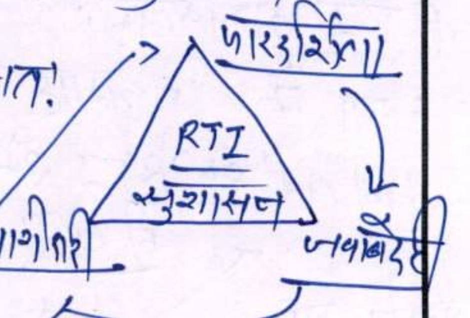

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा CIC व SIC को सशक्त करने की जरूरत है। थॉमस जेफरसन ने भी कहा है की "सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q6. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने भारत में जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस प्रकार परिवर्तित कर दिया है? इसकी पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How has Information and Communication Technology (ICT) transformed the governance landscape at the grassroots level in India? What are the key obstacles in leveraging its full potential? (Answer in 150 words) 10

ICT के प्रयोग से ई-गवर्नेंस की शुरुआत हुई। इससे सेवा वितरण और नागरिक इंटरफेस में व्यापक बढ़ोतरी देखी गई है। eg- JAM ट्रिनिटी द्वारा 1.2 अरब नागरिक जुड़े।

ICT का शासन के जमीनी स्तर पर प्रभाव

(1) जनकल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच बढ़ी
eg- DBT द्वारा 90 करोड़ लोग लाभान्वित

(2) सूचना का लोकतांत्रीकरण हुआ।
eg- mygov.in द्वारा नागरिक फीडबैक

(3) सुशासन के मूल्यों को साकार करने में सहायक। शासन में जनभागीदारी बढ़ी, पारदर्शिता, जवाबदेही शासन बना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ भ्रष्टाचार में कमी — जैसे- DBT के प्रयोग से 10 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ जिससे 25 बिलियन डॉलर की धन राशि की बचत हुई।

⑤ मोबाइल-गवर्नेंस को बढ़ावा मिला।

बाधाएं

* डिजिटल साक्षरता मात्र -10% ही है।
* डिजीटल डिवाइड की समस्या जैसे- मात्र 31% गाँव में इंटरनेट, 35% महिलाएं ही
* नई डिजिटल असमानता का उभार
* साइबर क्राइम में बढ़ोतरी जैसे- OTP द्वारा फ्रॉड के मामले
* डिजिटल ढांचा की कमी
* निजता के अधिकार जैसे- आरोग्य सेतु APP पर सवाल

आगे की राह — (1) डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म और भारत नेट परियोजना को बढ़ावा देना।

(2) डिजिटल साक्षरता अभियान को बढ़ाना होगा

(3) ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर ई-क्रांति UMANG APP जैसे प्रयास ताकि सुशासन को साकार किया जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q7. सिविल सेवाओं का राजनीतिकरण भारत में शासन के 'स्टील फ्रेम' को किस प्रकार नष्ट कर देता है? इस प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How does the politicization of the civil services corrode the 'steel frame' of governance in India? What measures can be implemented to counteract this effect? (Answer in 150 words) 10

भारतीय लोक सेवा को ~~जिसे~~ सरदार पटेल साहब ने स्टील फ्रेम कहा जो राजनीतिक-तटस्थता और निष्पक्षता से लोक कल्याणकारी राज्य के अग्रदूत की तरह काम करेंगे। लेकिन वर्तमान में लोक सेवकों का राजनीतिकरण एक गंभीर समस्या।

राजनीतिकरण का स्टील फ्रेम पर नकारात्मक प्रभाव

(1) निष्पक्ष चुनाव प्रभावित अनु. 326 के तहत स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक प्रावधान है। ५- इंदिरा गांधी v/s राजनारायण वाद -1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का मूल ढांचा माना

(2) लोक कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिकरण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

होने से अल्पसंख्यकों, वंचितों की अनदेखी होगी।

③ नोलन कमेटी के सार्वजनिक मूल्यों में वस्तुनिष्ठता एक अहम मूल्य है।
eg- T.N. शेषन की राजनीतिक-तटस्थता इसका उदा० होगा।

④ भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है जहाँ 2500 राजनीतिक दल है वहाँ लोकसेवक को कोड ऑफ कंडक्ट और संविधान के प्रति उत्तरदायी और प्रतिबद्ध होना चाहिए।

उपाय ① स्थानांतरण हेतु अलग सिविल सेवा बोर्ड का गठन eg प्रकाश सिंह वाद
② योग्यता, क्षमता को वफादारी से अधिक महत्व
③ कोड ऑफ एथिक्स को लागू करना।
④ ई-गवर्नेंस द्वारा वस्तुनिष्ठता व पारदर्शिता बनाना

अतः राजनीतिक तटस्थता के साथ काम करते हुए जन और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q8. लैंगिकता वृद्धावस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। भारत में सामाजिक अलगाव और वंचना का सामना करने वाली बुजुर्ग महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Gender is an important dimension of ageing. What measures can be taken to solve the problems of elderly women facing social alienation and deprivation in India? (Answer in 150 words) 10

भारत में बुजुर्गों की संख्या 9% है जो 2050 तक 20% होगी इनमें महिलाओं की संख्या अधिक होगी इसे ही वृद्धावस्था का महिलाकरण कहा जाता है।

बुजुर्ग महिलाओं की समस्याएं

- * 57% महिलाएं वैधव्य से ग्रस्त। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य सेवा नहीं
- * सामाजिक कुप्रथाओं का भार वृद्ध महिला पर अधिक eg- डायन प्रथा
- * विधवा को सामाजिक स्वीकार्यता न होना eg- सफेद वस्त्र
- संपत्ति अधिकार eg- 17%
- * अनदेखी और अप्रस्तुत योग्य मानकर नजरअंदाज करना।

* अनाथालय और वृद्धाश्रम को आपस में जोड़ना

* सामाजिक सुरक्षा
eg वृद्धावस्था पेंशन

* पोषण और स्वास्थ्य सेवा
eg- आंगनबाड़ी से जोड़ना

समाधान

* संपत्ति अधिकार
eg- पति की संपत्ति

→ अटल पेंशन

* सिल्वर डिविडेंड को बना देना eg- आशा सहयोगिनी के रूप

अतः वृद्धावस्था में लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु सामुदायिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा बनाना
eg- pm वयो वृद्ध योजना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q9. भारत और अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में भारतीय प्रवासी क्या भूमिका निभा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What role can the Indian diaspora play in fostering political and economic engagement between India and African countries? (Answer in 150 words) 10

अफ्रीका में भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
भारती प्रवासियों की 30-35 लाख आबादी अफ्रीका में निवास (विश्व मेत्रा.)

भारतीय प्रवासियों की भूमिका

↳ * भारतीय उत्पादों की मांग के कारण भारत के द्वारा अफ्रीका में 37 बिलियन डॉलर का निर्यात

* 300 भारतीय कंपनियाँ अफ्रीका में भारतीय डायस्पोरा द्वारा स्थापित

* श्रमिक और तकनीकी विशेषज्ञता के रूप में काम

* दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक भूमिका में अहम पद – अफ्रीकी कांग्रेस

* सांस्कृतिक राजदूत के रूप में काम करते हैं – गांधी जी की विरासत

* राजनीतिक प्रेरणा – नेल्सन मंडेला गांधी से प्रेरित थे।

अफ्रीका के आर्थिक व राजनीतिक विकास में भारतीयों की अहम भूमिका।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q10. अपने प्रारंभ के एक दशक से भी अधिक समय बाद, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लाभ, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए, भ्रामक साबित हुए हैं। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

More than a decade after its inception, the benefits of the Belt and Road Initiative have proven to be illusory, especially for developing countries. Comment. (Answer in 150 words) 10

BRI परियोजना चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना थी यह चीन की चेक बुक डिप्लोमेसी और डेब्ट ट्रैप नीति का पर्याय बनकर रह गई।

विकासशील देशों पर प्रभाव

(1) सम्प्रभुता का उल्लंघन के कारण अलोकप्रिय हुई eg श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को अपने नियंत्रण
eg मालदीव की सरकार में हस्तक्षेप

(2) नागरिक अधिकारों के हनन के कारण असफल eg पाकिस्तान में बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियर पर हमला

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ कर्ज के जाल में फँसाने की रणनीति की विफलता - नेपाल और बांग्लादेश पर चीनी कर्ज सर्वाधिक

① भारत के सागर, मौसम प्रोजेक्ट एशिया - अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और G7 के बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के कारण असफल रही।

अतः BRI अपने उद्देश्य में असफल रही

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q11. भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के समक्ष आने वाली वित्तीय बाधाओं पर चर्चा कीजिए। उनके राजस्व संसाधनों में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the financial constraints faced by the Panchayati Raj Institutions (PRIs) in India. What measures can be taken to augment their revenue resources? (Answer in 250 words) 15

भारत में 2.5 लाख से अधिक PRIs है जिनमें 31 मिलियन जनप्रतिनिधि शामिल है। PRIs को फंड, फंक्शन और फंक्सनरीज बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

PRIs की वित्तीय बाधाएं

(1) स्वंय के राजस्व स्रोत और संसाधन नही है। ध- मात्र (5%) राजस्व ही स्वंय द्वारा अर्जित किया जाता है।

(2) वित्तीय निर्भरता - केन्द्र और राज्यों के बद्ध अनुदान और स्पेशल ग्रांट पर निर्भरता (95%) से अधिक है।

(3) राजस्व संसाधनों का केन्द्रीकरण - GST में मनोरंजन कर, विज्ञापन कर को शामिल

करने से PRIs के अपने कर नहीं रहे

(4) बॉन्ड मार्केट में न्यूनतम हिस्सेदारी

(5) विधिक बाध्यताऐं - PRIs को उधार लेने के लिए राज्यों की अनुमति जरूरी

(6) आकांक्षा और ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले PRIs मात्र 4% है।

(7) भ्रष्टाचार के कारण PRIs की स्थिति खराब है - विलयवाड़ा पंचायत समिति ग्रांट

राजस्व संसाधन में वृद्धि करने के उपाय

↳ * संपत्ति कर को सशक्त करके स्थानीय स्तर पर एकत्रीत करने की जरूरत है

* म्युनीसिपल बांड और PRIs बांड को अपनाकर पूंजीबाजार का दोहन करना

* स्थानीय करों का हस्तांतरण PRIs को करना - स्टांप कर, कृषि आय कर

* राज्य वित्तीय आयोग का गठन समय पर करने की आवश्यकता है।

* ऑडिट और एकाउंटिंग प्रणाली को online करने की जरूरत है। विनोद राय की सिफारिश को लागू करते हुए PRIs को CAG के अंदर लाना।

* क्षमता निर्माण और सामुदायिक सशक्तीकरण जैसे- पुल्ड फाइनेंसिंग

PRIs को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाकर ही एजेंडा-2030 और विजन-2047 को साकार किया जा सकता है। जब तक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा तब तक नागरिकों का सशक्तीकरण नहीं होगा।

Q12. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 ECI की स्वतंत्रता को किस प्रकार प्रभावित करेगा? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role of the Election Commission of India (ECI) in ensuring free and fair elections in India. How will the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 impact the independence of the ECI? (Answer in 250 words) 15

संविधान के अनुच्छेद-324 व 326 तक तहत लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए 25 सितम्बर 1950 को ECI का गठन किया गया।

ECI की भूमिका

* राष्ट्रपति की चुनावी विवाद में सलाह
* मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाकर स्वच्छ चुनाव
* लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण में मदद
* अनु. 82 में परिसीमन आयोग को मदद करने की भूमिका
* RPA एक्ट 1951 के तहत धारा-29 में राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना
* अनु. 326 निष्पक्ष व समयबद्ध चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम -2023 का ECI की स्वतंत्रता पर प्रभाव

* नियुक्ति में चयन कमेटी में CJI की जगह प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री को लेने के कारण सरकार का प्रभुत्व हुआ।

* योग्यताओं का अनिश्चित होने के कारण CEC के पद का राजनीतिकरण होने की संभावना है।

* सर्च कमेटी में विधि मंत्री की अध्यक्षता से सीमित विकल्प होंगे।

* ECI में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जायेंगे अतः CEC की शक्तियों में असंगतता है।

* कार्यकाल - 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले हो। कार्यकाल के पश्चात अन्यत्र नियुक्ति पर रोक का प्रावधान अस्पष्ट

* अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया CEC की सलाह पर जो की H.C. जज के समान होनी चाहिए थी।

आगे की राह

↳ ECI को सशक्त करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कंधों पर अहम जिम्मेदारी है- 'उच्चतम न्यायालय" के निर्णय अनुसार काम हो।

* ECI को राजनीतिक दलों के पंजीकरण रद्द करने, वित्त पोषण पर निगरानी और आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने की शक्ति देना। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। अतः ECI को और प्रभावी करने की जरूरत है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ने भारत में वंचित समुदायों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और उन्हें भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 has played a significant role in preventing atrocities and providing protection against discrimination of marginalized communities in India. Analyse. (Answer in 250 words) 15

संविधान का अनुच्छेद -17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। साथ ही अनु. 14, 15 द्वारा समानता की स्थापना का प्रयास किया गया। SC/ST को जातीय भेदभाव से संरक्षण हेतु ही 1989 का अधिनियम लाया गया।

SC/ST (अत्याचार निवारण) अधि. 1989 की भूमिका व प्रासंगिकता

(1) जातीय अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर कठोर सजा का प्रावधान किया।

(2) जातीय भेदभाव से सुरक्षा प्रदान कर सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया

(3) बेलछी कांड -1977 जैसे जातीय संघर्ष

को रोकने में सफल हुआ।

(4) बंधवा मजदूरी, बेगार जैसे जाति आधारित कुप्रथाओं को समाप्त करने में।

(5) सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर भय मुक्त समाज की स्थापना की।

(6) सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक रहा व- समाज में समान भागीदारी को बढ़ावा दिया।

चुनौतियां →

* सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दुरुपयोग पर चिंता जताई
* दोष सिद्धी की निम्न दर
* राजनीतिक दुरुपयोग के कारण उत्पीड़न का प्रतीक बना
* लंबित मामलों में देरी से अप्रभावी हुआ।
* गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की गलत व्याख्या
* अग्रीम जमानत नहीं होना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह → * आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार कर मुद्दे के संवेदीकरण को समझना

फैक्ट फाइल
↳ SC - 16.8% आबादी
- ST - 8.6% आबादी
- 94% मामले गलत
- दोषसिद्धि - 10-6%

* दुरुपयोग को रोकने हेतु जागरूकता फैलाना

* SC/ST के सशक्तिकरण के लिए अन्य उपाय

अन्य कानून
↳ नागरिक अधिकार अधि. 1955

* सामुदायिक पुलिसिंग व पुलिस को मानवाधिकारों का प्रशिक्षण से प्रभावी

अतः सामाजिक न्याय और समरसता मूलक समाज के लिए भय मुक्त कानून प्रक्रिया जरूरी है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q14. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के कार्यों पर चर्चा कीजिए। महिलाओं की समस्याओं से निपटने में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होने से आयोग को क्या लाभ होता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the functions of the National Commission for Women (NCW). How does the Commission benefit from having the powers of a civil court in dealing with women's issues? (Answer in 250 words) 15

राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक संस्था है जो संसदीय कानून द्वारा गठित है। यह महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देकर लैंगिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास करता है।

NCW के कार्य और भूमिका

- * केन्द्र सरकार को महिलाओं के मुद्दों पर सलाह देना।
- निर्भया केस 2012 में आयोग की सक्रिय भूमिका से न्याय
- * लैंगिक नैतिकता को लागू करना
- → महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना
- * कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न POSH एक्ट -2013 के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना
- → * जागरूकता कार्यक्रम
- * समान व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु लैंगिक भेदभाव की शिकायत सुनना

न्यायालय की शक्तियों से NCW को निम्न लाभ होगा।

↳ ① सिविल कोर्ट की शक्तियों के तहत आयोग समन जारी कर सकेगा।

② दस्तावेजों की मांग और जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगने का अधिकार

③ निगरानी और शिकायत निवारण मामलों में पुलिस को निर्देश देने की शक्तियां मिली हैं।

④ दैनिक कार्यों के निस्तारण में सशक्त होगा ex- पीड़ित को राहत के आदेश देने में।

⑤ सरकार और न्यायालयों में लंबित मुद्दों की जानकारी मांग सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह

↳ वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत की रैंक 127 से सुधारने के लिए आयोग द्वारा सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

– POCSO, POSH एक्ट - 2013 और घरेलू हिंसा - 2005 जैसे कानूनों के सफल क्रियान्वयन में सामुदायिक-सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण में AI, IOT, बिग डेटा का प्रयोग कर समाज को अधिक समावेशी व सुरक्षित बनाने का प्रयास करना होगा।

Q15. भारत में बाल यौन शोषण के मुद्दे का समाधान करने में POCSO अधिनियम, 2012 की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Critically analyse the effectiveness of the POCSO Act, 2012 in addressing the issue of child sexual abuse in India. (Answer in 250 words) 15

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 92% मामले (POCSO एक्ट 2012 के तहत) में आरोपी निर्दोष साबित होता है जो इस कानून के अप्रभावी क्रियान्वयन की ओर संकेत करता है।

POCSO एक्ट की अप्रभावशीलता के कारण

- कानून का व्यापक दुरुपयोग होना
- लैंगिक और बाल अपराधों के प्रति कम जागरूकता
- संवेदीकरण के अभाव के कारण
- पुलिस की जाँच अपर्याप्त और गैर-पेशेवर होती है।
- लंबित मामलों की बड़ी संख्या
- POCSO कोर्ट और FTC की संख्या कम है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

POCSO कानून आज भी प्रासंगिक है —

POCSO एक्ट का महत्व और भूमिका

- FTC और POCSO कोर्ट द्वारा तेजी से निस्तारण
- लैंगिक और बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता का प्रसार हुआ
- सुरक्षित बचपन
- त्वरित न्याय
- बाल यौन अपराधों पर नियंत्रण हेतु जरूरी
- नाबालिगों के यौन उत्पीड़न पर रोक

आगे की राह

① पॉक्सो पोर्टल जैसी पहलों को बढ़ावा देना। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर निजता के अधिकार की रक्षा

② दोष सिद्धि की दर में सुधार हेतु बाल अधिकार समितियों को सशक्त

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ किशोर न्याय अधिनियम और POCSO एक्ट में विसंगति को दूर करना।

④ POCSO कोर्ट की संख्या बढ़ाकर विलंबित मामलो का निस्तारण करना क्योंकि देरी से मिला न्याय भी अन्याय ही होता है।

अतः POCSO एक्ट 2012 गंभीर यौन अपराधो के खिलाफ 20 वर्ष और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर इसे प्रभावी बनाता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q16. भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Critically evaluate the implementation of the Smart Cities Mission in India. (Answer in 250 words) 15

भारत में 100 स्मार्ट सिटी के शहरी आधारसंरचना को सशक्त करने के लिए अब तक 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन के घटक व महत्व

* म्युनसिपल गवर्नेंस को सशक्त और आत्मनिर्भर
* जलापूर्ति और पेयजल को बढ़ावा देना
* ठोस म्युनसिपल अपशिष्ट का प्रबंधन
* वहनीय आवास
* ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट
  eg- अल्ट्रा सोलर पार्क स्थापित
* अर्बन पब्लिक इन्फ्रा
* धारणीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना
  eg- दिल्ली में CNG बसों का संचालन

Call us : 8468022022, 9019066066 Visit us : www.visionias.in

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्मार्ट सिटी मिशन में चुनौतियाँ और बाधाएँ

↳ * फंडिंग की कमी → प्रत्येक शहर को 100 करोड़ रुपये देने का प्रावधान था लेकिन 50% शहरों को 100% राशि प्राप्त नहीं हुई।

* प्रोजेक्ट में विलंबन - स्मार्ट सिटी मिशन के 40% प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय से देरी पर चल रहे हैं।

* केन्द्रीकरण के कारण सभी शहरों पर वन साइज़ फिट फॉर ऑल के तहत एक समान मापदण्ड थोपे।

* पॉलिसी स्पेस का अभाव के कारण शहरों की स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इंदौर और सूरत के नगर नियोजन मॉडल को अपना कर अन्य शहरों में सिटी प्लानिंग गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए SDG-11, 12 के तहत Sustainable city and community के भारतीय लक्ष्यों को पूरा करना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q17. भारत में चरम निर्धनता में काफी कमी आई है, लेकिन स्वस्थ भोजन तक पहुंच अभी भी एक विलासिता का विषय बनी हुई है। स्वस्थ भोजन तक अपर्याप्त पहुंच के कारणों पर चर्चा कीजिए और उनका समाधान करने के उपाय सुझाइए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

While extreme poverty has declined considerably in India, access to healthy food still remains a luxury. Discuss the reasons for poor access to healthy food and suggest measures to overcome the same. (Answer in 250 words) 15

नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत ने 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है लेकिन NFHS-5 के आँकड़ों के अनुसार अभी भी स्वस्थ भोजन के अभाव में कुपोषण गंभीर समस्या है।

स्वस्थ भोजन का महत्व

↳ * FAO के अनुसार पोषण युक्त, संतुलित भोजन एक मानवाधिकार है।

* कुपोषण से मुक्त होने के लिए पोषण सुरक्षा और स्वस्थ भोजन आवश्यक है। ex- भारत में 22 करोड़ भुखमरी का शिकार लोग है तो 25.6% लोग मोटापा से

* फास्ट फुड का बढ़ना
- पश्चिमीकरण
eg- मैकडॉनाल्डीकरण

* पोषण सुरक्षा का अभाव
↳ 57% महिला एनीमिया
- 36.7% बच्चे स्टंटिंग

* फसल विविधता के अभाव के कारण
eg- मोटा अनाज की कमी।

स्वस्थ भोजन तक अपर्याप्त पहुँच के कारण

* गेहूं-चावल आधारित (PDS) सिस्टम

मिलावट खोरी

* नीतिगत कमियाँ
eg msp केवल गेहूं-चावल पर ही खरीद

* खाद्य सुरक्षा का अभाव
eg- 22 करोड़ भूखमरी (FAO)

स्वस्थ भोजन हेतु समाधान

↳ ① खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए PDS में विविधता लाना
eg- मिड-डे-मिल में मोटा अनाज

② कुपोषण से मुक्ति हेतु राइस फोर्टिफिकेशन जैसे कदम उठाना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ नमक का आयोडीनीकरण और सुपर बनाना जैसे प्रयोग से पोषण युक्त भोजन

③ मिलावट और रियूज ऑयल को रोकना होगा eg MDH मसालों में मिलावट का मामला

④ फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए बागबानी, एकीकृत फसल पद्धति को को बढ़ावा देना होगा।

⑤ पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी, PM-मातृत्व वंदन, पोषित माँ जैसी योजनाओं से कुपोषण मुक्त भारत की स्थापना

अतः स्वस्थ भोजन को अधिकार बनाकर SDG-1 और SDG-2 2030 Hunger को समाप्त करना होगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q18. भारत में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Examine the role of publicly funded health insurance in improving health outcomes in India. (Answer in 250 words) 15

भारत में out of pocket expenditure - 43.7% है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य बीमा के अभाव से हर साल 5.5 करोड़ लोग हेल्थ पर व्यय के कारण गरीबी में ग्रस्त होते है।

सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा की भूमिका

→ ① इन्श्योरेंस पेनिट्रेशन मात्र 4.2% है। इसे बढ़ाने के लिए जरूरी है।

② नीति आयोग की मिसिंग मिडिल रिपोर्ट के अनुसार भारत की 30% आबादी किसी भी तरह के बीमा लाभ से वंचित है।

③ स्वास्थ्य पर OOPE के कारण गरीबी के दुष्चक्र में फँसे लोगों को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मुक्त करने हेतु जरुरी है

(4) SDG-3 वहनीय व गुणवत्तापूर्ण हेल्थ फैसेलिटी के लिए स्वास्थ्य बीमा

(5) 70% स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदत्त की जाती है जो अत्यधिक महंगी है।

चुनौतियां
- (1) बीमा घनत्व अत्यधिक कम
- (2) निजी निवेश सीमित
- (3) सरकारी कम्पनियों का एकाधिकार
- (4) जागरूकता की कमी
- (5) हेल्थ सेक्टर पर बजट का मात्र 2.1% व्यय होता है।

समाधान और कदम
- # आयुष्मान भारत योजना के तहत 20 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किए।
- # राजस्थान सरकार की

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चिरंजीवी स्कीम को सम्पूर्ण देश में लागू करना होगा।

बीमा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना eg- FDI लिमिट 74%.
eg- LIC का IPO लाँच

जागरूकता को बढ़ावा देकर डिजीटल हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाया जा सकता
eg- ई-इंश्योरेंस पोर्टल बनाना

सरकार द्वारा एकीकृत सार्वभौमिक बीमा नीति का निर्माण करना।

अतः स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देकर हेल्थ में सार्वभौमिक वहनीय पहुँच को बढ़ाया दिया जाये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q19. भारत की 'पड़ोस प्रथम (Neighbourhood First)' नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने में किस हद तक सफल रही है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent has India's 'Neighbourhood First' policy been successful in enhancing its relations with the neighbouring countries? (Answer in 250 words) 15

2014ई. मे पड़ोस प्रथम नीति द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप और अन्य पड़ोसी राष्ट्रों को वरीयता नीति अपनायी गई

भारत के पड़ोसी

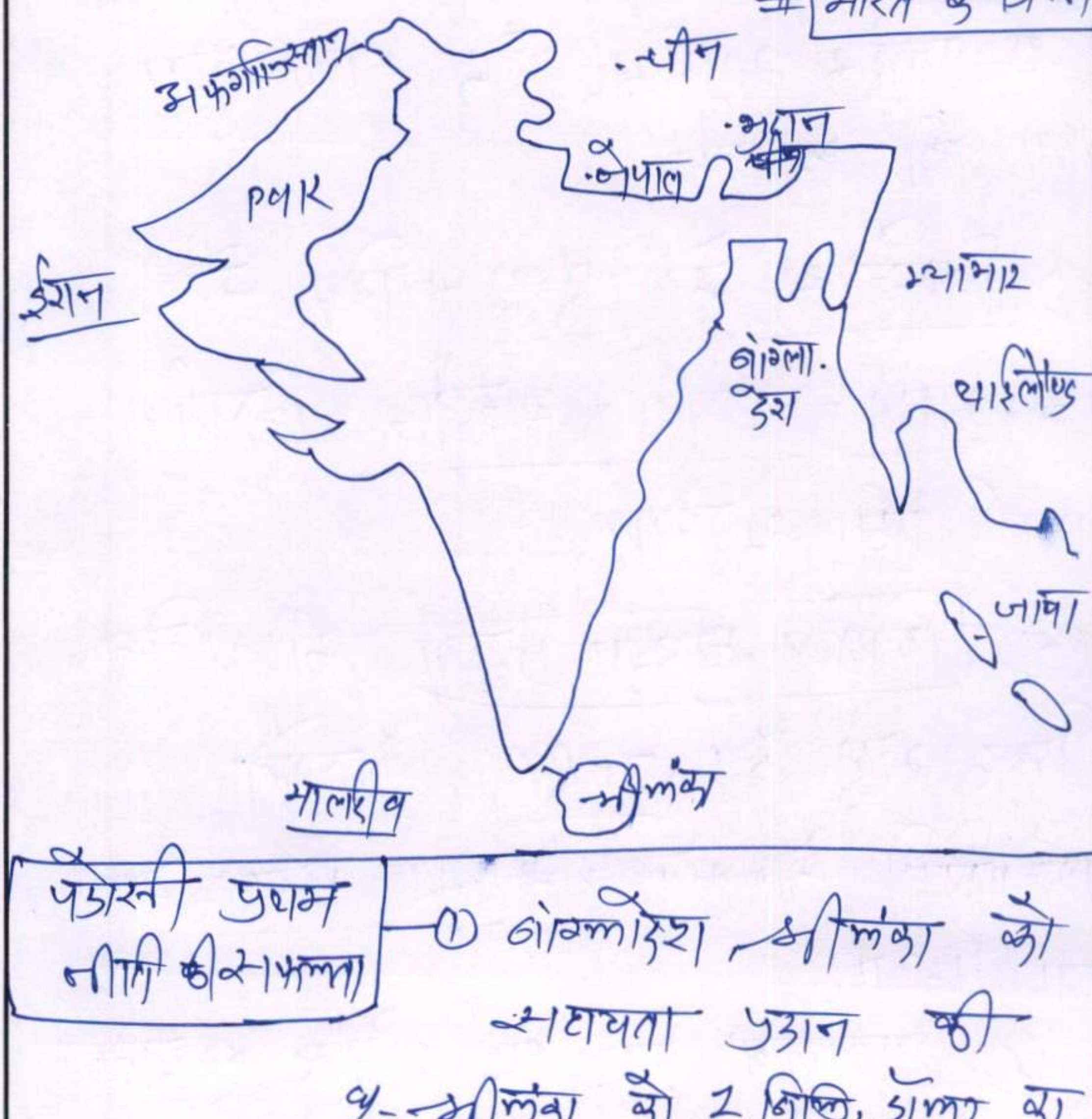

पड़ोसी प्रथम नीति की सफलता

(1) बांग्लादेश, श्रीलंका को सहायता प्रदान की
e.g.- श्रीलंका को 2 बिलि. डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② नेपाल के संबंधो में तनाव को कम कर पुन: रोटी- बेटी के सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ा
eg- 750 मिलि. डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट

③ भूटान के सबसे बड़े आयातक, निर्यातक और व्यापारिक भागीदार के साथ रक्षा प्रदाता की भूमिका

④ बिम्सटेक को पुन: सक्रिय करते हुए - भारत - म्यामार - थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग की शुरुआत

⑤ निवल सुरक्षा प्रदाता की भूमिका में हिन्द महा. में ZORA, कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, सागर पहल को लागू किया।

⑥ मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, हार्ड इम्पैक्ट कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम।

(चुनौतियाँ) — ① चीन की आक्रामकता और बढ़त को कम करने में चुनौती

② पाकिस्तान से द्विपक्षीय संबंधों में संघर्ष बढ़ा

③ सार्क संगठन निष्क्रिय हुआ
जैसे 2014 काठमांडू सम्मेलन के बाद बैठक नहीं

④ मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन और चीन के पक्ष वाली सरकार

⑤ बांग्लादेश में शेख हसीना पर निर्भरता और अब तख्तापलट

(आगे की राह) — ① रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए गुजराल सिद्धांत और सागर विजन से काम लेना होगा।

② बिम्सटेक को बढ़ावा देकर भारत को दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी गैप को भरना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q20. पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों के भारत पर पड़ने वाले उल्लेखनीय प्रभावों को रेखांकित करते हुए इसके क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Examine the effects of escalating conflicts in West Asia on regional and global stability, highlighting the significant repercussions for India. (Answer in 250 words) 15

पश्चिमी एशिया में इज़राइल-फिलिस्तीन, यमन-हूती, लेबनान-हिजबुल्ला और ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच भारत के आर्थिक, सामरिक व सुरक्षा हित प्रभावित हो रहे हैं।

पश्चिमी
एशिया

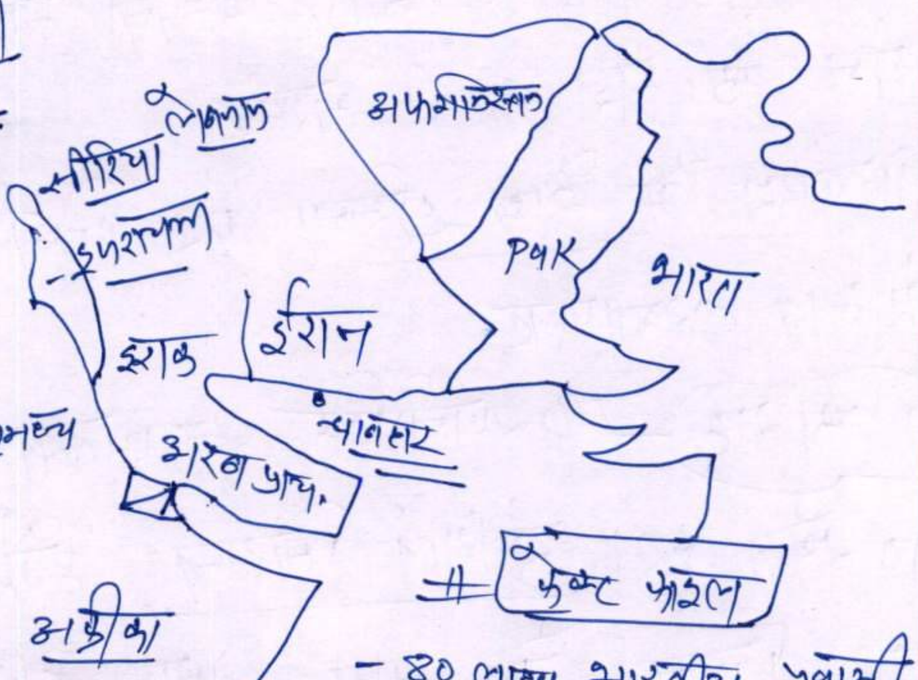

फैक्ट फ़ाइल
- 80 लाख भारतीय प्रवासी
- 60% ऑयल और गैस

भारत पर प्रभाव → (1) पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है

* खाड़ी देश भारत की 60% गैस और क्रूड ऑयल की मांग को पूरा करते

② आर्थिक रूप से खाड़ी देशों में भारत का द्विपक्षीय व्यापार 151 बिलियन डॉलर है। जो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होता है। संघर्ष से भारतीय समुद्री संचार मार्ग प्रभावित

③ समुद्री पायरेसी में बढ़ोतरी से सुरक्षित मार्ग पर हूती विद्रोह का हमला * सशस्त्र गुटों का और पुन: * समुद्री नौवहन पर नकारात्मक प्रभाव

क्षेत्रीय प्रभाव
- ← वैश्विक आतंकवाद का पुन: उद्भव
- → * मुहाजिरीयों के खेल की पुन:
- ↓ * राजनीतिक अस्थिरता

(वैश्विक प्रभाव) – ईरान - इजरायल वॉर शुरु से परमाणु खतरा

→ USA और ईरान गतिरोध से आर्थिक संरक्षणवाद

चीन - रूस - ईरान के गठबंधन से विभाजित विश्व युग शुरु

→ अस्थिरता, शरणार्थी समस्या और जलवायु समस्या।

(आगे की राह) – I2U2 जैसे मंचों को व्यापक करना

→ अब्राहम अकोर्ड को सही नियत से लागू करना।

UN की UNSC को समावेशी बनाकर संघर्षों का समाधान प्रयोग डिप्लोमेसी से।